

प्रेषक,

एम०सी० उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 11 जून, 2004

विषय: भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1981 के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र मैमो/2004/रा०आ० दिनांक 12 अप्रैल, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला फोरम में परिवाद दाखिल करने हेतु प्राप्त होने वाले निर्धारित शुल्क/धनराशि को राजकोष में जमा करने हेतु खाद्य विभाग के लिए आवंटित प्राप्ति का लेखाशीर्षक-1456-सिविल पूर्ति-800-अन्य प्राप्तियाँ-01-खाद्य और रसद विभाग की प्राप्तियाँ-03-अन्य विविध प्राप्तियाँ के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी जायेंगी। कृपया अपनी प्राप्ति को उक्त लेखाशीर्षक में जमा करने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 499/वित्त अनु०-3/2004 दिनांक: 09 जून, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या: 237 (1)/XIX/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त नियंत्रक, खाद्य, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
5. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर०सी० लोहनी)
उप सचिव।